The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15—मार्च 21, 2014 (फाल्गुन 24, 1935) No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15—MARCH 21, 2014 (PHALGUNA 24, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची पृष्ठ सं. पुष्ठ सं. भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार के प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकत पाठ (ऐसे पाठों को छोडकर जो भारत अधिसूचनाएं. 191 के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों होते हैं)..... और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी नियम और आदेश..... अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नितयों, भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं. महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल 311 भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... अधिसूचनाएं. भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और के बिल तथा रिपोर्ट. डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं...... प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों छोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक द्वारा जारी की गई अधिसचनाएं, आदेश, विज्ञापन नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और और नोटिस शामिल हैं...... 2737 उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों 301 (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को को दर्शाने वाला सम्पुरक.

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	467	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
Part I—Section 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence		PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	*
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi	*	Attached and Subordinate Offices of the Government of India	249
language, of Acts, Ordinances and Regulations PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	2 1 9
Committee on Bills		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the			2737
Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the		Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	301
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I — खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2014

सं. 3-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2014 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

- श्री धीरज माथुर उप अधीक्षक तिहाड़ केन्द्रीय जेल दिल्ली
- श्री निरंजन दास
 अधीक्षक
 सिर्कल जेल, चौधवार, कटक
 ओडिसा
- 2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

सुरेश यादव राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

सं. 4-प्रेज/2014--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2014 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

- श्री प्रसाद राव गद्दम हैड वार्डर उप-जेल, गिद्दालुर आंध्र प्रदेश
- श्री माधव राव भोंसले सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल बिलासपुर छत्तीसगढ़
- श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा हैड वार्डर केन्द्रीय जेल, बिलासपुर छत्तीसगढ़

- श्री शिवली राम मीणा हैड वार्डर 615 तिहाड़ केन्द्रीय जेल दिल्ली
- श्री होशियार सिंह वार्डर 710 तिहाड़ केन्द्रीय जेल दिल्ली
- श्री भिखनखान कदुखान बहेलिम जेलर महानिरीक्षक जेल कार्यालय, अहमदाबाद गुजरात
- श्री जगजीत सिंह अपर महानिरीक्षक जेल महानिदेशक का कार्यालय हरियाणा
- श्री हरीश कोटवाल अधीक्षक जिला जेल कटुआ जम्मू एवं कश्मीर
- श्री हिलाल अहमद राथर उप अधीक्षक जिला जेल अनंतनाग जम्मू एवं कश्मीर
- 10. श्री जी. वीरभद्र स्वामी जेल उप महानिरीक्षक एवं मुख्य अधीक्षक केन्द्रीय जेल, बेलगाम कर्नाटक
- 11. श्री बी. टी. ओबालेशप्पा सहायक अधीक्षक ओपन एयर जेल, कोरमंगला कर्नाटक
- 12. श्री डी. सत्यराज अधीक्षक विशेष उप जेल, नेयात्तिंकारा केरल

- 13. श्री के. वसंत कुमार हैड वार्डर केन्द्रीय जेल, कन्नुर केरल
- 14. श्री ई. कृष्णदास हैड वार्डर उप जेल, पोन्नानी केरल
- 15. श्री मदन कमलेश उप अधीक्षक जिला जेल, शहडोल मध्य प्रदेश
- 16. श्री शिव कुमार टेकम वार्डर उप जेल, पाटन मध्य प्रदेश
- 17. श्री ओम प्रकाश शर्मा वार्डर उप जेल, विदिशा मध्य प्रदेश
- 18. श्री नामदेव बाजीराम गायकवाड सूबेदार ठाणे केन्द्रीय जेल, ठाणे महाराष्ट्र
- 19. श्री दयानेश्वर दशरथ काले जेलर ग्रेड-1 अहमदनगर जिला जेल महाराष्ट्र
- श्री मनोहर प्रकाश भिसे हवलदार कोल्हापुर जिला जेल (सिटी) महाराष्ट्र
- श्री दिलीप राउ पाटिल सूबेदार जिला जेल अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुणे महाराष्ट्र
- 22. श्री पुरुषोत्तम बलीराम मून हवलदार नागपुर केन्द्रीय जेल महाराष्ट्र
- 23. श्री एस. जयन्त सिंह वार्डर मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल मणिपुर

- 24. श्री डब्ल्यू, जिन मैतेई वार्डर मणिपुर केन्द्रीय जेल, सजीवा मणिपुर
- 25. श्री एस. एल. हाओपु वार्डर मणिपुर केन्द्रीय जेल, इम्फाल मणिपुर
- 26. श्री बीरेन चौ. डे. हैड वार्डर विलियमनगर मेघालय
- श्री सुरेश कुमार मोहापात्रा हैड वार्डर सर्किल जेल, सम्बलपुर ओडिशा
- 28. श्रीमती सोभागिनी सिंह सहायक मैट्रन नारी बंदी निकेतन, सम्बलपुर ओडिशा
- 29. श्री निरंजन साहू जेल कल्याण अधिकारी सर्किल जेल, सम्बलपुर ओडिशा
- 30. श्री के. रेंगन सहायक जेलर महिला उप जेल, तिरुवरूर तिमलनाडु
- 31. श्री एम. के. मुरुगेसन मुख्य हैड वार्डर केन्द्रीय जेल, मदुरै तिमलनाडु
- 32. श्री एम. राजा मुख्य हैड वार्डर उप-जेल, पिरुमंगलम तमिलनाडु
- 33. श्री पी. धनसेकरन ग्रेड-1 वार्डर (यूजी) केन्द्रीय जेल, सेलम तिमलनाडु
- 34. श्री नागेन्द्र सिंह चौहान हैड वार्डर केन्द्रीय जेल, आगरा उत्तर प्रदेश

- 35. श्री राम रतन वर्मा वार्डर केन्द्रीय जेल, बरेली उत्तर प्रदेश
- 36. श्री रिवन्दर कुमार प्रजापित हैड वार्डर जिला जेल, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश
- 37. श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा वार्डर केन्द्रीय जेल, बरेली उत्तर प्रदेश
- 38. श्री एसके. गियासुद्दीन अहमद वार्डर अलीपुर सीसीएच पश्चिम बंगाल
- 39. श्री सांति पदा पांडा वार्डर अलीपुर सीसीएच पश्चिम बंगाल
- 2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4(iii) के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

सुरेश यादव राष्ट्रपति के विशेष कार्याधिकारी

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी 2014 .

संकल्प

सं. 1/7/2012-कपास--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2013 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास सलाहकार बोर्ड परामर्शदात्री सिमिति में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:

- (1) श्री अठोट सुब्बा राव, पेडककानिमंडल, तक्केलापादु, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश।
- 2. दिनांक 10 जनवरी, 2014 का संकल्प सं. 1/7/2012-कपास उपर्युक्तानुसार संशोधित किया जाता है।
- 3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 09 जनवरी, 2013 की मूल अविध सूचना संख्या 1/7/2012-कपास में दर्शाई गई बोर्ड की अविध की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे।
- 4. आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की जाए।

5. यह भी ओदश किया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

> आर. के. श्रीवास्तव अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2014

संकल्प

सं. 9/4/2010-टीयूएफएस--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा दिनांक 25 जून, 2012 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास यार्न सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:--

- (1) श्री कोटिपल्ली राधाकृष्ण मूर्ति, डी. सं. 6-21-31, 13/2, अरुणदलपत, गुंट्रर-522002, आंध्र प्रदेश।
- (2) डॉ. रामचंद्र रेड्डी एलुरी, पुत्र श्री वाई. जी. वीरा रेड्डी, डी. नं. 10-104-जी 63, श्री साई नगर, जवाहर नगर कालोनी, मार्कापुरम, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश-523316 ।
- 2. बोर्ड के सदस्य बोर्ड को अपनी सेवा 31 मार्च, 2014 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, देंगे।
- 3. सिचवालय सहायता वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रदान की जाएगी। आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को संप्रेषित की जाए।
- 4. यह आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के श्रीवास्तव अवर सचिव

संकल्प

सं. 1/7/2012-कपास--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2013 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास सलाहकार बोर्ड परामर्शदात्री सिमिति में निम्निलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:--

(1) श्री नल्लूरी सांबासिवा राव, पुत्र श्री वेंकैया, कोमतानेनीवरी पालेम, चिलकालुरिपेता (मंडलम), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश।

- (2) डॉ. जड़ी वेंकट नारायण गौड़, बाबू मेमोरियल अस्पताल, गणेश नगर, गिद्दलूर-523357, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश।
- (3) श्री विजय कुमार रेड्डी, चिल्ला, विला नंबर 5 आदित्य फोर्ट व्यू, पुप्पाला गुदा, मणिकोंडा के पास, हैदराबाद-500089।
- 2. दिनांक 18 फरवरी, 2014 का संकल्प सं. 1/7/2012-कपास उपर्युक्तानुसार संशोधित किया जाता है।
- 3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 09 जनवरी, 2013 की मूल अविध सूचना संख्या 1/7/2012-कपास में दर्शाई गई बोर्ड की अविध की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे।
- 4. आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की जाए।
- 5. यह भी आदेश किया जाता है संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. श्रीवास्तव अवर सचिव

दिनांक 3 मार्च 2014

संकल्प

सं. 1/7/2012-कपास--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2013 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास सलाहकार बोर्ड परामर्शदात्री सिमित में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:--

- (1) श्री डी. नरसिम्हा रेड्डी, फ्लैट नंबर 201, आरती रेजीडेंसी, लक्ष्मी नगर कालोनी, साईदाबाद, हैदराबाद-500059, आंध्र प्रदेश।
- 2. दिनांक 28 फरवरी, 2014 का संकल्प सं. 1/7/2012-कपास उपर्युक्तानुसार संशोधित किया जाता है।
- 3. पुनर्गठित बोर्ड के सदस्य दिनांक 09 जनवरी, 2013 की मूल अविध सूचना संख्या 1/7/2012-कपास में दर्शाई गई बोर्ड की अविध की समाप्ति तक सेवा में रहेंगे।
- 4. आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को प्रेषित की जाए।

5. यह भी आदेश किया जाता है संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

> आर. के. श्रीवास्तव अवर सचिव

संकल्प

सं. 9/4/2010-टीयूएफएस--भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा दिनांक 25 जून, 2012 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा गठित कपास यार्न सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से शामिल करने का निर्णय लेते हैं:--

- (1) सुश्री लक्ष्मी रेड्डी, पुत्री श्री ओबी रेड्डी, निवासी 7/3/1, नेहरू नगर, ढोल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश।
- 2. बोर्ड के सदस्य बोर्ड को अपनी सेवा 31 मार्च, 2014 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, देंगे।
- 3. सिचवालय सहायता वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रदान की जाएगी। आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को संप्रेषित की जाए।
- 4. यह आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. के. श्रीवास्तव अवर सचिव

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय नई दिल्ली-110066, दिनांक 25 फरवरी 2014

संकल्प

सं. के-12012/5/5/2013/योजना--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के संकल्प संख्या के-12012/5/5/2013-यो. एवं अनु./के माध्यम से दो वर्ष की अविध के लिए पुनर्गठित किया गया था। भारत सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में निम्नलिखितानुसार नये गैर-सरकारी सदस्य को शामिल करने का निर्णय लिया है जबिक दिनांक 27 दिसम्बर, 2013, 27 जनवरी 2014, 10 फरवरी 2014, 13 फरवरी 2014 एवं 20 फरवरी 2014 के संकल्प के अनुसार गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी पदाधिकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत् रहेंगे।

 श्री बी राधा कृष्णा नागाभुषणम-गांव सिंगानापुडी का हैमलैट मंडावली मंडल, जिला-कृष्णा-521345 आंध्र प्रदेश

- मौ. तैयब

 नगरीपर-गांव

 मोहम्मदाबाद गोहना
 जिला-मऊ, उत्तर प्रदेश
- श्री चिंतापल्ली सुब्बाराव पेडापलपरू, मुडीनेपल्ली मंडल वाया मोटुरू, जिला-कृष्णा आंध्र प्रदेश
- श्री उदय किरन देवीनेनी विला नं. 24, आदित्य फोर्ट वियू पुपल्ला गुडा, मनीकोंडा के नजदीक हैदराबाद
- श्री नहरीसेट्टी श्रीहरी
 नं. 9-63-36, ईस्लामपैट,
 विजयवाडा-1, आंध्र प्रदेश
- श्री सी मनगा राजु जिला-प्रेसीडेंट, माला महानादू जिला पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश)
- श्री के. एन. तुलसी राव सीतारामपुरम, नरसापुर मंडल, जिला पश्चिमी गोदावरी-534280 (आंध्र प्रदेश)

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में बोर्ड की मौजूदा क्षमता 86 सदस्य होगी जिसमें अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 26 सरकारी सदस्य और 60 गैर-सरकारी सदस्य हैं।

तथापि, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के संकल्प में अभिलिखित सभी अन्य निबन्धन और शर्तें यथावत् और अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

> एस. एस. गुप्ता विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2014

सं. 11-78/2013-स्कूल-5--स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आईसीटी @ स्कूल योजना वर्ष 2004-05 में शुरू तथा दिसम्बर, 2010 में संशोधित की गई थी तथा हाल ही में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की समावेशी योजना में समायोजित की गई है। स्कूलों में आईसीटी के उपयोग का अवसर उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा (2012) के लिए आईसीटी की राष्ट्रीय नीति विकसित की है।

2. स्कूल प्रणाली में आईसीटी को शामिल करने के लिए अधिक महत्व, विशेष रूप से शिक्षा में मिशन मोड परियोजना के मद्देनजर तथा शिक्षा में आईसीटी के सभी पहलुओं पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन के लिए एतद्द्वारा स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर एतद्द्वारा तत्काल राष्ट्रीय म्रोत समूह का निम्नानुसार गठन किया जाता है:--

	लए एतद्द्वारा स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर एतद्द्वारा त समूह का निम्नानुसार गठन किया जाता है:	ात्काल रा
1.	सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य
3.	उप कुलपति, एनयूपीईए	सदस्य
4.	अतिरिक्त सचिव एसई (प्राथमिक शिक्षा), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
5.	अतिरिक्त सचिव ई ई (शिक्षक शिक्षा), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, एस ई-1, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, शिक्षण सहायक प्रौद्योगिकी, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, एस ई-2, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव, डीआईटी	सदस्य
10.	महानिदेशक, ई आर एन ई टी या नामित	सदस्य
11.	महानिदेशक, सीडीएसी या नामित	सदस्य
12.	महानिदेशक, एनआईसी या नामित	सदस्य
13.	अध्यक्ष, सीबीएसई	सदस्य
14.	अध्यक्ष, एनआईओएस	सदस्य
15.	आयुक्त, केवीएस	सदस्य
16.	आयुक्त, एनवीएस	सदस्य
17.	अध्यक्ष, एनसीटीई	सदस्य
18.	*प्रधान सचिव, शिक्षा, कर्नाटक	सदस्य
19.	*प्रधान सचिव, शिक्षा, केरल	सदस्य
20.	*प्रधान सचिव, शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
21.	एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि	सदस्य
22.	एक पूर्वोत्तर राज्य के प्रतिनिधि	सदस्य
23.	डॉ. डी. बी. पाठक, आईआईटी मुंबई,	सदस्य

एनएमईआईसीई

24. डॉ. जी. नागर्जुन, एचबीसीएसई,

25. श्री जी. गुरूमूर्ति, आईटीफॉर चेंज

टीआइएफआर, मुंबई (मेटास्ट्रडियो)

सदस्य

सदस्य

26.	डॉ. सावित्री सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय (क्रिएटिव कॉमन)	सदस्य
27.	श्री आर श्रीधर, एज्यूकेशन इनिशेटिव	सदस्य
28.	श्री एस. आनंद, ग्रेमनर (डाटा एनालिसटिक्स)	सदस्य
29.	श्री गिरीश श्रीवास्तव, एनएएसएससीओएम, (परियोजना परिबंधन)	सदस्य
30.	श्री रघुरमन, अमृत विश्व विद्यापीठ विश्वविद्यालय (वर्चुअल प्रयोगशालाएं)	सदस्य
31.	प्रो. जितेन्द्र शाह, आईआईटी मुंबई (जीआईएस)	सदस्य
32.	निदेशक, एसएसए (सीएएल प्रभारी)	सदस्य
33.	निदेशक/उप सचिव (टीई)	सदस्य
34.	निदेशक, आरएमएसए और आईसीटी, डीएसई एंड एल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
35.	परामर्शदाता, आईसीटी आरएमएसए-टीएसजी	सदस्य
36.	संयुक्त निदेशक, सीआईईटी, एनसीईआरटी (एनआरओईआर और आईसीटी पाठ्यक्रम) (जेडी, सीआईईटी, एनसीईआरटी की अनुपस्थिति में निदेशक, आरएमएसए और आईसीटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सदस्य संयोजक होंगे)	सदस्य संयोजक

*जिन राज्यों/संघ क्षेत्रों ने आईसीटी के उपयोग में सफलता दर्शाई है, उन्हें विशेष आमंत्रितों के रूप में बैठक में आमंत्रित किया जाए।

- 3. एनआरजी के विचारार्थ विषय होंगे:
- (i) राष्ट्र की शिक्षा नीति के अनुरूप आईसीटी के समुचित उपयोग के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परामर्श।
- (ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल प्रणाल में उपलब्ध साधन और नई आईसीटी प्रौद्योगिकी अर्थात: शिक्षक और शिक्षा प्रशासन को कार्यनीति पर परामर्श देना।
- (iii) राज्यों में कार्यान्वयन की निगरानी मूल्यांकन और मार्गदर्शन की कार्यनीति की सिफारिश करना।
- (iv) मुक्त शिक्षा-संसाधन के राष्ट्रीय कोष के विकास और प्रबंधन को सहयोगी मंच पर लाने के लिए सभी सार्वजनिक एजेंसियों, शिक्षा का सभी सार्वजनिक एजेंसियों, शिक्षा समूह और वैयक्तिकों को शामिल कर सहयोगी मंच पर लाने के लिए मार्गदर्शन करना।
- (v) व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया और स्कूलों में आईसीटी के पाठ्यक्रम सहित आईसीटी की स्थापना और उपयोग में स्कूल प्रणाली के पदाधिकारियों का सहायता के लिए मार्गदर्शन करना।
- (vi) स्कूल की भिन्न स्थितियों, विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, उपयुक्त हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी के उपयोग पर अध्ययन या सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समूह की स्थापना पर मार्गदर्शन करना।
- (vii) आरएमएसए के तहत् माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता दखल/आईसीटी घटक के लिए निगरानी अनुदेश द्वारा प्रदत्त निगरानी/मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा।

- (viii) संस्थाओं और अन्य हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना।
- 4. क्रम सं. 18--31 के सदस्यों की सदस्यता दो वर्ष की अविध या उनके स्थान पर किसी नए सदस्य को नामित किए जाने तक, जो भी बाद में हो, के लिए होगी।
- 5. जब भी आवश्यक होगा एनआरजी विचारार्थ विषयों का विस्तार किया जा सकता है। एनआरजी निर्धारित कार्य या विशिष्ट मुद्दों के समाधान पर उप-समिति के गठन के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है।
- 6. एनआरजी की प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक होगी।
- 7. एनआरजी को सचिवालयी सहायता एनसीईआरटी (सीआईईटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- एनआरजी जैसा उपयुक्त विशिष्ट समझे मामलों के निपटान के लिए ऐसे उप-समृहों का गठन कर सकता है।

कैरालिन खोंगवर देशमुख निदेशक (आरएमएसए/आईसीटी)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2014 संकल्प

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा परिषद्

सं. 1-1/2013-ईसीसीई--भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की प्रणाली तैयार करने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) नीति के तहत् राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् की परिकल्पना की गई है राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय अवधारणा तथा रणनीति तैयार करेगी और व्यापक ईसीसीई तंत्र स्थापित करके भारत में ईसीसीई की नींव को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करेगी। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत् राष्ट्रीय स्तर की संस्था होगी, जो प्रशिक्षण पाट्यचर्या की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धतियां उपलब्ध कराएगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

प्रारंभ में यह एक सलाहकार तथा निरीक्षण निकाय होगा जो धीरे-धीरे ईसीसीई के क्षेत्र में व्यवस्थित सुधारों के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय बन जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपिसड), ईसीसीई परिषद् के लिए जानकारी जुटाएगा तथा शुरू में स्थान और संभार तंत्र की अपेक्षित सहायता के साथ इसकी मदद करेगा। इसी प्रकार, निपिसड के क्षेत्रीय केन्द्रों में ईसीसीई से संबद्ध कार्यक्रम प्रणाली, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) तथा विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारियों के माध्यम से क्षेत्रीय ईसीसीई परिषदों की स्थापना की जा सकती है। प्रणाली में तालमेल लाने के लिए राज्य ईसीसीई परिषदों को गठित करने के लिए भी राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. उद्देश्य

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अवधारणा तथा प्रथा बनाना है। इसे एक व्यापक ईसीसीई प्रणाली स्थापित करके तथा समेकित ढांचा विकसित करके प्राप्त किया जाएगा जो बहु-माडल तथा बहु-घटक उपायों, दीर्घकालिक डाटा संकलन और आयोजना, तथा अधिक कारगर अंतर-क्षेत्रक सेवा प्रदायगी की पद्धतियों और प्लेटफार्मों को सुगम बनाते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा।

परिषद् ईसीसीई एवं संबंधित नीतियों को बढ़ावा देगी तथा पेशेवरों एवं देखभालकर्ताओं सिहत परिवारों, समुदायों तथा पूरे समाज में साक्ष्य आधारित प्रथाओं को आगे बढ़ाएगी। यह विनियामक तंत्र भी निर्धारित करेगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पद्धित के मानदंडों तथा मानकों और इससे संबंधित मामलों के लिए मानदंडों एवं मानकों के उपयुक्त अनुपालन का सुनिश्चय करेगी।

3. अवधारणा

यह स्वीकार करते हुए कि बाल विकास सतत् एवं संचयी प्रक्रिया है जो जीवन चक्र के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, व्यापक बाल विकास की दिशा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा साक्ष्य आधारित संकल्पना और प्रथाओं को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना।

4. लक्ष्य

- उत्तरदायी पणधारियों में ईसीसीई के परिणामों के लिए समान जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता का सुनिश्चिय करना, साक्ष्य आधारित साधन, संसाधन, प्रक्रियाएं, पद्धतियां तथा जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना।
- ईसीसीई के सभी पहलुओं में सुधार के लिए प्रणालियां एवं नेटवर्क विकसित करना, सहायता देना एवं स्थापित करना।
- सतत् गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ परिणामों तथा संकेतकों को विनियमित करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।

5. परिणाम

- सर्वांगीण, समेकित तथा ईष्टतम बाल विकास प्राप्त करना और विकास में विलंब पर रोक लगाना।
- गुणात्मक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं की व्यापक तथा स्थाई प्रणालियां।
- ईसीसीई क्षेत्र के बारे में सार्वजिनक जागरूकता तथा पेशेवराना अंदाज में सुधार।

6. अधिदेश

- ईसीसीई के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए नीतियां, कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना।
- 2. ईसीसीई में व्यवस्थित सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ईसीसीई की जानकारी का विकास करना, प्रसार करना और उपयोग करना।
- नई रणनीतियों तथा विकल्पों की खोज करना तथा ईसीसीई में नवाचारों को व्यापक बनाने और उन्हें कायम रखने के तरीकों का पता लगाना।

7. परिषद् के कार्य

परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो उसे ईसीसीई के मानकों के निर्धारण और उन्हें कायम रखने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की नीतियों, रूपरेखाओं तथा अन्य प्रावधानों का योजनाबद्ध और समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों तथा राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद् निम्नलिखित कार्य कर सकती है:

- (क) नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संबंध में सरकार की उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में सरकार को रणनीति संबंधी निदेश तथा परामर्श देना।
- (ख) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के लिए समग्र आयोजना का नेतृत्व करना।
- (ग) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी ईसीसीई गतिविधियों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अच्छी तरह नियोजित, कार्यान्वित एवं मूल्यांकित हों।
- (घ) ईसीसीई सेवा प्रदायगी में साम्यपूर्ण एवं तर्कसंगत विधियां लाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- (ङ) सभी छोटे बच्चों के इष्टतम ईसीसीई सेवाएं सुनिश्चित करना।
- (च) देश में ईसीसीई प्रावधानों तथा उनकी सुलभता और उपलब्धता का समन्वय करना तथा उनकी मानीटरिंग करना।
- (छ) परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशानिर्देशों एवं मानकों के कार्यान्वयन की जांच करना और आवधिक आधार पर समीक्षा करना तथा संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से सलाह देना।
- (ज) ऐसी प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो ईसीसीई के लिए जोखिम कारकों को घटाएं तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों को बढ़ावा दें।
- (झ) नए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए और भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टाफिंग प्रणाली (पैटर्न) तथा स्टाफ अर्हता के लिए ईसीसीई संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
- (ञ) ईसीसीई संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्र विकसित करना।
- (ट) विभिन्न स्तरों पर ईसीसीई पेशेवर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- (ठ) ईसीसीई कार्यक्रमों द्वारा प्रयुक्त खेल उपकरण, खेल सामग्री, खेल-स्थान, फर्नीचर, पुस्तकों तथा बाल साहित्य आदि के लिए मानदंड तथा मानक निर्धारित करना।
- (ड) ईसीसीई प्रावधानों के व्यावसायीकरण तथा बच्चों के विकास की दृष्टि के अनुपयुक्त शिक्षा को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाना।
- (ढ) शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर सलाह देना।

- (ण) प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिकों के लिए कारगर कोचिंग तथा समकक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रणालियां स्थापित करना।
- (त) पूरे देश में ईसीसीई के लिए जीवंत, गतिशील अनुसंधान नेटवर्क तथा सूचना की हिस्सेदारी के लिए सुगम्य ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म विकसित करना।
- (थ) ईसीसीई से संबंधित बृहत्तर क्षेत्र में ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हों या केन्द्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए हों, या संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सहयोग से हों।

8. परिषद की संरचना

इस परिषद् में सभी संबद्ध विभागों/मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों, सभ्य समाज के संगठनों, व्यावसायिकों, पेशवरों, शिक्षाविदों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं आदि का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

सामान्य परिषद्

	*	
1.	मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	सदस्य, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	(कार्यपालक) उपाध्यक्ष
4.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अयोग	सदस्य
5.	सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
12.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव
13.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
14.	वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
15.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईसीसीई परिषदों के पांच (5) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे	सदस्य
16.	गृह विज्ञान कॉलेजों के मानव संसाधन विकास विभागों के दस (10) संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा में ज्ञात रुचि एवं योगदान वाले ईसीसीई विशेषज्ञ जिन्हें भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा	सदस्य

17. प्रतयेक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सदस्य एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से ईसीसीई के स्वतंत्र प्रभार वाले डब्ल्यूसीडी मंत्रालय/ विभाग से राज्यों के पांच (5) प्रतिनिधि, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे

सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष/(कार्यपालक) उपाध्यक्ष की अनुमित से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। परिषद् के निर्णय के अनुसार और/या समय-समय पर सरकार के निदेश के अनुसार बैठकें होंगी।

कार्यकारिणी समिति

1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष)	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार, डब्ल्यूसीडी, योजना आयोग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (ईसीसीई), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य संयोजक
4.	संयुक्त सचिव (आईसीडीएस, पोषण), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, मानव विकास संसाधन मंत्रालय (प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा, एसएसए)	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
9.	प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर पूर्व) से एक के हिसाब से 5 राज्यों से डब्ल्यूसीडी और/या ईसीसीई के सचिव, जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे।	सदस्य
10.	क्षेत्रीय सिमतियों, विशेषज्ञों एवं पेशेवर निकायों के छह (6) प्रतिनिधि	सदस्य
11.	निदेशक, निपसिड	सदस्य
12.	निदेशक, एनसीईआरटी	सदस्य
;	अध्यक्ष की अनमति से विशेषज्ञों/विकास साझेदारों के	ो सहयोजित ।

अध्यक्ष की अनुमति से विशेषज्ञों/विकास साझेदारों को सहयोजित एवं आमंत्रित किया जा सकता है।

9. कार्यकाल

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

पदेन सदस्यों से भिन्न आकस्मिक रिक्तयों को उस प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा जिसने उन सदस्यों को मनोनीत किया था जिनका स्थान रिक्त हुआ है। आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत व्यक्ति कार्यकाल की ऐसी शेष अवधि के लिए परिषद का सदस्य होगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान को वह भरेगा, सदस्य रहता।

10. विचारार्थ विषय

राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् को तकनीकी विशेषज्ञता एवं दक्षता निर्मित करने और ईसीसीई के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसे विषयों पर जिन्हें संगत समझा जा सकता है, विषयपरक/तकनीकी समितियां गठित/सृजित करने का अधिकार होगा।

कार्यकारिणी सिमिति शासी (सामान्य) परिषद् के निर्णयों को निष्पादित एवं कार्योन्वित करेगी। यह परिषद् के निर्णयों को लागू करने के लिए अधिकृत होगी। यह परिषद् के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद् के निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक उप सिमितियां गठित कर सकती है।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों की सिमितियां स्थापित की जाएंगी तथा आबंटित कार्य संपन्न करेंगी एवं राज्य में परिषद् के कार्यों के कार्यान्वयन एवं समग्र नीति कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अनुसार राज्य परिषदों की सिमितियां स्थापित की जाएंगी तथा जिला एवं निचले स्तर पर कार्यान्वयन का समग्र रूप से मानीटरन करेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

> ह./- अपठनीय सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

सं. ए-50013/167/2013-प्रशा.-IV--राष्ट्रपित महोदय, हाल ही में उभर कर आए सोशल मीडिया एवं समसामियक मीडिया के जिरए सूचना का प्रसार करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक नए मीडिया सैल की स्थापना करते हैं। संयुक्त सिचव (नीति एवं प्रशासन) इस नव गठित सैल के समग्र प्रभारी होंगे जिन्हें विशेष कार्य अधिकारी (सी) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त सैल को पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (आरआरटीडी), जिसे नए मीडिया विंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, द्वारा कार्यात्मक और प्रचालनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।

2. 'नए मीडिया विंग' में पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के सभी मौजूदा कर्मचारी/अधिकारी तथा उसकी अवसंरचना शामिल होगी। मंत्रालय के सोशल मीडिया सैल के साथ वर्तमान में संलग्न भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों को एतद्द्वारा 'नए मीडिया विंग' के साथ संलग्न किया जाता है। सोशल मीडिया सैल के वे अधिकारी 'नए मीडिया विंग' के अपर महानिदेशक (एडीजी) को सीधे रिपोर्ट करेंगे जो आगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे।

3. यह दिनांक 04 सितम्बर, 2013 से प्रभावी होगा।

बी. बंधोपाध्याय अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2014

No. 3-Pres/2014—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 2014, to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel:—

- Shri Dheeraj Mathur Dy. Supdt. Tihar Central Jail Delhi.
- Shri Niranjan Das Superintendent Circle Jail, Cuttack at Choudhwar Odisha.
- 2. These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Distinguished Service.

SURESH YADAV OSD to the President of India

No. 4-Pres/2014—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 2014 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel:—

- Shri Prasad Rao Gaddam
 Head Warder
 Sub-Jail, Giddalur, Prakasam District
 Andhra Pradesh.
- Shri Madhaw Rao Bhonsle Asstt. Jail Supdt., Central Jail, Bilaspur Chhattisgarh.
- Shri Laxmi Narayan Sharma Head Warder Central Jail, Bilaspur Chhatisgarh
- Shri Shivli Ram Meena Head Warder 615 Tihar Central Jail Delhi.
- Shri Hoshiar Singh Warder 710 Tihar Central Jail Delhi.
- Shri Bhikhankhan Kadukhan Bahelim Jailor Officer of the IG Prisons, Ahmedabad Gujarat
- 7. Shri Jagjit Singh Additional I.G. O/o D. G. Prisons Haryana.

- Shri Harish Kotwal Superintendent District Jail Kathua Jammu & Kashmir.
- Shri Hilal Ahmed Rather Deputy Superintendent District Jail Anantnag Jammu & Kashmir.
- Shri G. Veerabhadra Swamy
 Dy. Inspector General of Prisons and Chief Superintendent
 Central Prison, Belgaum
 Karnataka.
- Shri B. T. Obaleshappa
 Assistant Superintendent
 Open Air Jail, Koramangala
 Karnataka.
- Shri D. Sathyaraj Superintendent Special Sub Jail, Neyyattinkara Kerala.
- Shri K. Vasantha Kumar Head Warder Central Prison, Kannur Kerala.
- Shri E. Krishnadas Head Warder Sub Jail, Ponnani Kerala.
- Shri Madan Kamles
 Deputy Superintendent
 District Jail, Shadol
 Madhya Pradesh.
- Shri Shiv Kumar Taikam Warder Sub Jail, Patan Madhya Pradesh.
- Shri Om Prakash Sharma Warder
 Sub Jail, Vidisha Madhya Pradesh.
- Shri Namdeo Bajirao Gaikwad Subedar Thane Central Prison, Thane Maharashtra.
- Shri Dnyaneshwar Dashrath Kale Jailor Gr. I Ahmednagar District Prison Maharashtra.
- Shri Manohar Prakash Bhise Havaldar Kolhapur District Prison (City) Maharashtra.

- Shri Dilip Rau Patil
 Subedar
 DJ Jail Officer Trg College
 Pune.
- Shri Purushottam Baliram Moon Havaldar Nagpur Central Prison Maharashtra.
- Shri S. Jayanta Singh Warder Manipur Central Jail, Imphal Manipur.
- Shri W. Jin Meitei
 Warder
 Manipur Central Jail, Sajiwa
 Manipur.
- Shri S. L. Haopu
 Warder
 Manipur Central Jail, Imphal
 Manipur.
- Shri Biren Ch. Dey Head Warder Williamnagar Meghalaya
- Shri Suresh Kumar Mohapatra Head Warder Circle Jail, Sambalpur Odisha.
- Smt. Sobhagini Singh
 Assistant Matron
 Nari Bandi Niketan, Sambalpur Odisha.
- Shri Niranjan Sahoo
 Prison Welfare Officer
 Circle Jail
 Sambalpur, Odisha
- Shri K. Rengan
 Assistant Jailor
 Women Sub Jail, Thiruvarur
 Tamil Nadu.
- 31. Shri M. K. Murugesan Chief Head Warder Central Prison, Madurai Tamil Nadu.
- 32. Shri M. Raja Chief Head Warder Sub Jail, Thirumangalam Tamil Nadu.
- 33. Shri P. Dhanasekaran Grade-I Warder (UG) Central Prison, Salem Tamil Nadu

- Shri Nagendra Singh Chauhan Head Warder Central Jail, Agra Uttar Pradesh.
- Shri Ram Ratan Verma Warder Central Jail, Bareilly Uttar Pradesh.
- Shri Ravinder Kumar Prajapati Head Warder District Jail, Firozabad Uttar Pradesh.
- Shri Lakshman Prasad Sharma Warder Central Jail, Bareilly Uttar Pradesh.
- 38. Shri S.K. Giyasuddin Ahamed Warder Alipore Central Correctional Home West Bengal
- Shri Santi Pada Panda Warder Alipore Central Correctional Home West Bengal.
- 2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

SURESH YADAV OSD to the President of India

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 18th February 2014

RESOLUTION

No. 1/7/2012-Cotton—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Consultative Committee of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even number dated 9th January, 2013 with immediate effect:—

- (i) Shri Athota Subba Rao, Pedkakani Mandal, Takkellapadu, Guntur District, Andhra Pradesh.
- 2. The Resolution No. 1/7/2012-Cotton dated 10th January, 2014 stands modified to the extent stated above.
- 3. The members of the reconstituted Board will serve till the expiry of the term of Board as indicated in the original notification No. 1/7/2012-Cotton dated 9th January, 2013.
- 4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.

5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA Under Secy.

The 28th February 2014 RESOLUTION

No. 9/4/2010-TUFS—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Cotton Yarn Advisory Board, constituted vide Notification No. 9/4/2010-TUFS dated 25th June, 2012 with immediate effect:—

- (i) Shri Kotipalli Radhakrishna Murthy,D. No. 6-21-31,13/2, Arundelpet,Guntur-522002,Andhra Pradesh.
- (ii) Dr. Ramachandra Reddy Yeluri, S/o Shri Y. G. Veera Reddy, D. No. 10-104-G 63, Sri Sai Nagar, Jawahar Nagar Colony, Markapuram, Prakasam District, Andhra Pradesh-523316.
- 2. The member of the Board will serve on the Board upto 31st March, 2014 or until further orders whichever is earlier.
- 3. Secretariat Assistance will be provided by the Office of the Textile Commissioner, Mumbai. Ordered that the copy of this Notification be communicated to all concerned.
- 4. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA Under Secy.

RESOLUTION

No. 1/7/2012-Cotton—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Consultative Committee of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even number dated 9th January, 2013 with immediate effect:—

- (i) Shri Nalluri Samba Siva Rao, S/o Shri Venkaiah, Komatanenivari Palem, Chilakaluripeta (Mandalam), Guntur District, Andhra Pradesh.
- (ii) Dr. Jadi Venkata Narayana Goud, Babu Memorial Hospital, Ganesh Nagar, Giddalur-523357, Prakasam District, Andhra Pradesh.

- (iii) Shri Vijay Kumar Reddy Chilla, Villa No. 5, Aditya Fort View, Puppala Guda, Near Manikonda, Hyderabad-500089.
- 2. The Resolution No. 1/7/2012-Cotton dated 18th February, 2014 stands modified to the extent stated above.
- 3. The members of the reconstituted Board will serve till the expiry of the term of Board as indicated in the original notification No. 1/7/2012-Cotton dated 9th January, 2013.
- 4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.
- 5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA Under Secy.

The 3rd March 2014

RESOLUTION

No. 1/7/2012-Cotton—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Consultative Committee of the Cotton Advisory Board, constituted vide Resolution of even number dated 9th January, 2013 with immediate effect:—

- (i) Shri D. Narasimha Reddy, Flat No. 201, Aarthi Residency, Laxminagar Colony, Saidabad, Hyderabad-500059, Andhra Pradesh.
- 2. The Resolution No. 1/7/2012-Cotton dated 28th February, 2014 stands modified to the extent stated above.
- 3. The members of the reconstituted Board will serve till the expiry of the term of Board as indicated in the original notification No. 1/7/2012-Cotton dated 9th January, 2013.
- 4. Ordered that the copy of this Resolution be communicated to the concerned.
- 5. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA Under Secy.

RESOLUTION

No. 9/4/2010-TUFS—The Competent Authority in the Government of India hereby decides to include the following as member of the Cotton Yarn Advisory Board, constituted vide Notification No. 9/4/2010-TUFS dated 25th June, 2012 with immediate effect:—

- (i) Ms. Laxmi Reddy,D/o Shri Obi Reddy,R/o 7/3/1,Nehru Nagar, Dhole,District Kurnool,Andhra Pradesh.
- 2. The member of the Board will serve on the Board upto 31st March, 2014 or until further orders whichever is earlier.
- 3. Secretariat Assistance will be provided by the Office of the Textile Commissioner, Mumbai. Ordered that the copy of this Notification be communicated to all concerned.
- 4. Ordered also that it be published in the Gazette of India.

R. K. SRIVASTAVA Under Secy.

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 25th February 2014

RESOLUTION

No. K-12012/5/5/2013/Planning—The All India Handicrafts Board was re-constituted vide Resolution No. K-12012/5/5/2013/Planning dated 27th December, 2013, for tenure of two years. The Government of India has decided to Induct following as new Non Official Members of All India Handicrafts Board, while retaining all officials and Non Official Members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide Resolution dated 27th December 2013, 27th January 2014, 10th February 2014, 13th February 2014 & 20th February 2014.

- Shri B Radha Krishna Nagabhushanam Village, Hamlet of Singanapudi Mandavalli Mandal Krishna District-521345 Andhra Pradesh
- 2. Mohd. Tayyab Village Nagripar Mohamdabad Gohna District-Mau Urrat Pradesh
- 3. Shri Chintapalli Subbarao Pdapalaparru Mudinepalli Mandal Via Moturu Krishna District Andhra Pradesh
- 4. Shri Uday Kiran Devineni Villa No. 24, Aditya Fort View, Puppala Guda Near Manikonda Hyderabad

- Shri Naharisetty Srihari
 9-63-36, Islampet,
 Vijayawada-1,
 Andhra Pradesh
- 6. Shri C. Managa Raju District President Mala Mahanadu West Godavari Distt. Andhra Pradesh
- Shri K.N. Tulasi Rao Seetharampuram Narsapur Mandal, West Godawari Distt.-534280 Andhra Pradesh

The present strengh of the Board shall be 86 Members comprising of Chairman, Co-Chairperson, Vice-Chairperson, 14 official Members, 8 Institutional Members including Member Secretary and 60 Non-official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 27th December 2013 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

S.S.GUPTA Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Schools Education & Literacy)

New Delhi, the 22nd January 2014

No. F. 11-78/2013-Sch-5—The ICT @ School scheme of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development was launched in the year 2004-05 and revised in December 2010, and has been recently subsumed within the umbrella Scheme of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA). In order to widen the scope of use of ICT in schools, MHRD has developed in National Policy of ICT for School Education (2012).

2. To provide a greater thrust to the infusion of ICT into the school system, Particularly in the light of the Mission Mode Project on Education and to guide the MHRD on all aspects of ICT in education, the National Resource Group on ICT in School Education is hereby constituted immediate effect as follows:—

1. Secretary, Department of School Chairperson Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development

2. Director NCERT Member

3. Vice Chancellor, NUPEA Member

4.	Additional Secretary SE (Elementary Education), Department of SE&L	Member
5.	Additional Secretary EE (Teacher Education), Department of SE&L	Member
6.	Joint Secretary, SE-1, Department of SE&L	Member
7.	Joint Secretary, Technology Enabled Learning, Department of Higher Education, MHRD	Member
8.	Joint Secretary, SE-II Department of SE&L	Member
9.	Joint Secretary, Deit Y	Member
10.	Director General, ERNET or Nominee	Member
11.	Director General, CDAC or Nominee	Member
12.	Director General, NIC or Nominee	Member
13.	Chairman, CBSE	Member
14.	Chairman, NIOS	Member
15.	Commissioner, KVS	Member
16.	Commissioner, NVS	Member
17.	Chairman, NCTE	Member
18.	*Principal Secretary, Education, Karnataka	Member
19.	*Principal Secretary, Edcuation, Kerala	Member
20.	*Principal Secretary, Education Himachal Pradesh	Member
21.	Representative of One Union Territory	Member
22.	Representative of one North Eastern State	Member
23.	Dr. D.B. Phatak, IIT Mumbai, NMEICT	Member
24.	Dr. G. Nagarjuna, HBCSE, TIFR, Mumbai (metastudio)	Member
25.	Sh. G. Gurumurthy, IT for Change	Member
26.	Dr. Savithri Singh, Delhi University (Creative Commons)	Member
27.	Shri R. Sridhar, Education Initiatives	Member
28.	Sh. S. Anand, Gramener (Data Analytics)	Member
29.	Sh. Girish Srivastava, NASSCOM, (Project Management)	Member
30.	Sh. Raghuraman, Amrita Vishwa Vidyapeetham University (Virtual Laboratories)	Member
31.	Prof. Jitendra Shah, IIT Mumbai (GIS)	Member
32.	Director, SSA (in charge of CAL)	Member
33.	Director/Deputy Secretary (TE)	Member

- 34. Director, RMSA And ICT, DSE&L, MHRD Member
- 35. Consultant, ICT RMSA-TSG Member
- 36. Joint Director, CIET, NCERT (NROER and Member ICT Curriculum) (Director, RMSA and Convenor ICT, MHRD will be the member in the absence JD, CIET, NCERT)

*States/UTs that have demonstrated success in use of ICT may be invited as special invitees for the meetings.

- 3. The Terms of References for the NRG shall be:-
 - Advise the MHRD on the appropriate use of ICT to further the goals and objectives in tune with the education policy of the Nation.
 - ii) Advise the MHRD of the Strategies of how best to leverage available and new ICT technologies for use in the school system, for g, teachers and education administrators.
- iii) Recommend strategies to monitor, evaluation and guide the implementation in the states.
- iv) Guide the development management of the National Repository of Open Educational Resources into a collaborative platform involving all public agencies, education into a collaborative platform involving all public agencies, educational group and individuals.
- v) Guide the process of professional development and render support to functionaries of the school system in the establishment and use of ICT, including the curriculum for ICT in Schools.
- vi) Guide the Establishment of expert group for undertaking studies or making recommendation on use of appropriate hardware, software, connectivity for the diverse school situations, particularly in remote areas.
- vii) Review the Monitoring/Evaluation Reports provided by Monitoring Institutions for the Quality Interventions/ICT component in Secondary Education under RMSA.
- viii) To enhance co-ordination between institutions and other stakeholders.
- 4. The membership for members Sl No. 18—31 will be for a period of two years or till the time a new member is nominated in his/her place, whichever is later.
- The scope of the temrs of reference of the NRG may be expanded as and when needed. The NRG may invite specialists to assist it with specific tasks or constitute sub-committees to address specific issues.
- 6. The NRG will meet at least twice in every calendar year.
- The secretarial support to the NRG will be provided by NCERT (CIET).
- 8. NRG may constitute such sub-groups for dealing with sepcific areas, as it may deem appropriate.

CARALYN KHONGWAR DESHMUKH Director (RMSA/ICT)

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th February 2014 RESOLUTION

National Early Childhood Care and Education Council

No. 1-1/2013-ECCE—The National Early Childhood Care Education (ECCE) Policy envisages a National Early Childhood Care and Education (ECCE) Council for laying the system of early childhood care and education in India. The National ECCE Council will lay the national vision and strategy for ECCE and would contribute to strengthen the foundation of ECCE programmes in India by establishing a comprehensive ECCE system. The National ECCE Council would be a national level organization under the Ministry of Women and Child Development, Government of India for providing systems of training, curriculum framework, standards and related activities; and promoting action research with an aim to improve the field of early childhood care and education.

It will be initially an advisory and oversight body, gradually becoming an autonomous regulatory body for systemic improvements in the field of ECCE. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) would play the role of knowledge repository for the ECCE Council and support initially with requisite support of accommodation and logistics. Similarly, Regional ECCE Councils may be established at the NIPCCD Regional Centres through synergistic partnerships with ECCE related programme system, State Councils for Education Research and Training (SCERTs)/State Institutes of Education and Training (SIETs) and Universities. States would also be encouraged to form State ECCE Councils to bring in systemic synergies.

2. Objective

The main objective of the National ECCE Council is to embed the concept and practice for holistic and integrated development of the young children in the age group of 0-6 years with requisite quality. This would be achieved by establishing a comprehensive ECCE system and developing an integrated framework that would contribute to strengthen the foundation of ECCE programmes in India by facilitating and supporting multimodal and multicomponent interventions; long term data collection and planning; and more efficient intersectoral service delivery mechanisms and platforms.

The council would promote ECCE and related polices and advance evidence-based practices in families, communities and society at large including professionals and caregivers. It will also lay down the regulatory mechanism and ensure proper adherence to norms and standards in the early childhood development system and for mattters connected therewith.

3. Vision

To firmly establish evidence based concept and practices of early childhood care and education towards holistic child development by recognizing that child development is continuous and cumulative that follows a lifecycle approach.

4. Goals

- To promote shared responsibility of ECCE outcomes among responsible stakeholders
- To ensure quality, make available evidence-based tools, resources, processes, methodologies and advocacy material
- To develop, support and eatsblish systems and networks for improvement in all facets of ECCE.
- To regulate, supervise and monitor ECCE services with a commitment to continuous quality improvement.

Outcomes

- Achieve holistic, integrated and optimal child development and prevention of development delays
- Comprehensive and sustainable systems of quality early childhood care and education services
- Improvement in public awareness and professionalism of ECCE sector

6. Mandate

- 1. Formulation of policies, implementation guidelines for ECCE programmes and services.
- 2. Development, dissemination, application of knowledge of ECCE for strengthening and bringing in systemic reforms in ECCE.
- 3. Explore new Strategies and alternatives and identifying ways and meens to scale and sustain innovations in ECCE

7. Functions of the Council

It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and co-ordinated development of early childhood care and education policies, frameworks and other provisions for the determination and maintenance of standards for ECCE and for the purposes of performing its functions under the national ECCE Policy, the Council May:—

- a. Issue strategic directions and advisories to the Government of improving the implementation of policies and in the matter of preparation of suitable plans and programmes of Government with regard to early childhood care of education
- b. Lead overall planning for the National ECCE Policy
- c. Lead and delegate all ECCE activities specified under the National ECCE Policy and ensure that they are well planned, implemented and evaluated
- d. Lay down guidelines to bring in equity and rational methods in ECCE service delivery

- e. Ensure optimum ECCE services for all young Children
- f. Co-ordinate and monitor ECCE provisions and their access and availability in the country
- g. Examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and suitably advise the institutions
- h. Encourage establishment of systems that reduce risk factors for ECCE and promote protective factors/measures for ECCE
- Lay down guidelines for compliance by ECCE institutions, for starting new programmes, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualification
- j. Evolve suitable performance appraisal system, norms and mechanism for enforcing accountability on ECCE institutions
- k. Lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as an ECCE professional at various levels
- Set norms and standards for play equipment, play materials, play space, furniture, books, children's literature etc. used by ECCE programmes
- m Take all necessary steps to prevent commercialisation of ECCE provisions and developmentally inappropriate education of children
- n. Advise on the development of training programmes on early childhood care and education for educators and other staff in educational institutions
- o. Establishing systems for providing effective coaching and peer-to-peer support for early childhood professionals
- p. Developing a vibrant, dynamic research network in ECCE across the country and an accessible knowledge management platform for information sharing
- q. Take such action in the larger field relating to ECCE as may be appropriate or entrusted to it by the Central Government, or in collaboration with relevant line Ministries and authorities.

8. Structure of the Council

The Council will have wider representations from all converging Departments/Ministries, representatives of NGOs, civil society organizations, professionals, practitioners, academicians, child rights activists etc.

General Council

Minister, Ministry of Women and Chairperson
 Child Development (President)

- . Member, WCD, Planning Commission Vice-President
- 3. Secretary, Ministry of Women and Child (Executive)
 Development VicePresident
- 4. Chairperson, National Commission for Member Protection of Child Rights
- Secretary, Ministry of Human Resource Member Development
- Secretary, Ministry of Health and Family Member Welfare
- 7. Secretary, Department of Ayush, Ministry Member of Health and Family Welfare
- Secretary, Ministry of Social Justice and Member Empowerment
- 9. Secretary, Ministry of Rural Development Member
- 10. Secretary, Ministry of Panchayati Raj Member
- 11. Secretary, Expenditure Member
- 12. Joint Secretary (ECCE) Member Secretary
- Joint Secretary, (ICDS Nutrition) Ministry Members of Women and Child Development
- 14. Financial Advisor, Ministry of Women Member and Child Development
- 15. Five (5) Chairpersons/Vice Chairpersons Members of State/UTs ECCE Councils by rotation every two years
- 16. Ten (10) Deans/Head of Departments of Members Human Development Departments in Home Science Colleges/ECCE experts with known interest and contribution in the field of Early Childhood Care and Education nominated by Government of India
- 17. Five (5) representatives of States from Members WCD Ministry/Department, one from each region (North, South, East, West and North East), with independent charge of ECCE by rotation for every two years.

The Member Secretary may co-opt and invite ECCE experts, Development partners etc. with the permission of the Chairperson (President)/(Executive) Vice President of the Committee. The meetings will be held as decided by the council and/or as directed by Government from time-to-time.

Executive Committee

- Secretary, Ministry of Women and Chairperson Chairperson of the Executive Committee)
 Chairperson of the Executive
- Senior Advisor/Advisor, WCD, Planning Member Commission

Members

3.	Joint Secretary (ECCE), Ministry of	Member
	Women and Child Development	Convenor

- 4. Joint Secretary, (ICDS, Nutrition), Members Ministry of Women Child Development
- JS & FA, Ministry of Women and Child Member Development
- 6. Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development (in-charge, Elementary Education, SSA)
- 7. Joint Secretary, Ministry of Health Member and Family Welfare
- 8. Joint Secretary, Ministry of Social Member Justice and Empowerment
- Secretaries of WCD and/or ECCE from 5 states, 1 from each region, (North, South, East, West and North East) by rotation every two years
- 10. Six (6) Respresentatives from, Regional Members
 Committees, experts and professional
 bodies
- 11. Director, NIPCCD Member
- 12. Director, NCERT Member

Experts/Development partners may be co-opted and invited with the permission of the Chairperson.

9. Tenure

The tenure of the nominated members shall be two eyars.

The casual vacancies, other than ex-officio members, shall be filled by the authority which nominated those members whose place falls vacant.

The person nominated to a casual vacancy shall be a member of the Council for the residue of the term for which the member whose place he/she fills would have been a member.

10. Terms of Reference

The National ECCE Council will have powers to create/constitute thematic/technical committees on themes as may be considered relevant, to build technical expertise and competence and to meet the emerging challenges in the field of ECCE.

The Executive Committee will execute and implement the decisions of the governing (General) Council. It will be empowered to implement the decisions of the Council. It

may constitute thematic Sub-Committee as per directions/ decisions of the Council for furthering the functions of the Council.

The Committees of the Regional Councils would be established as per National ECCE Policy and would perform its assigned task and do overall monitoring of the implementation of functions of the Council & overall policy implementation in the State.

The Committees of the State Councils would be established as per National ECCE Policy and perform the overall monitoring of the implementation in the districts and below level.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministeries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resoloution be published in the Gazette of India for general information.

Sd/- Illegible Secretary

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th December 2013

No. A-50013/167/2013-Admn.IV—The President is pleased to set up a New Media Cell in the Ministry of Information & Broadcasting to disseminate the information through newly emergent social media and concurrent media. Joint Secretary (Policy & Administration) will be the overall Incharge of this newly established Cell who will be assisted by OSD (C). The functional and operational support to the above Cell will be provided by erstwhile Research Reference and Training Division (RRTD), which has been replaced by the New Media Wing.

- 2. The 'New Media Wing' will include all the existing staff and infrastructure of erstwhile Research Reference and Training Division. The Indian Information Service (IIS) Group-'A' and Group 'B' officers presently attached with Social Media Cell of the Ministry are hereby attached with the 'New Media Wing'. Those officers of Social Media Cell will directly report to Additional Director General (ADG) of 'New Media Wing' who will, in turn, report to the Ministry of Information & Broadcasting.
 - 3. This will have effect from 04th September, 2013.

B. BANDYOPADHYAY Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014 PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014 www.dop.nic.in